भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 511

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में पीएमएवाई-यू

511. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के आरंभ से अब तक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्मित और पूरा किए गए/सुपुर्द किए गए मकानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं सहित कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत कुल कितने मकान बनाए गए हैं;

(ग) स्वस्थानिक मलिन बस्ती पुनर्वास, जो पीएमएवाई-यू का एक ऊर्ध्वाधर घटक है, के तहत वर्तमान में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) क्या सामाजिक आवासों के निर्माण योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने शहरी क्षेत्रों में आवास से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से

क्रियान्वित की जाती है। बीएलसी घटक के अंतर्गत आवासों का निर्माण व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा उनकी अपनी भूमि पर किया जाता है, एएचपी और आईएसएसआर का कार्यान्वयन सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किया जाता है तथा सीएलएसएस के अंतर्गत लाभार्थी निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित आवासों को प्राप्त करने/खरीदने के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

15.07.2024 के स्थिति के अनुसार देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा सभी घटकों के अंतर्गत कुल 118.63 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन है और 85.04 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।आईएसएसआर घटक के तहत अब तक कुल 2,95,598 आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2,26,710 आवास निर्माणाधीन हैं और 1,63,031 आवास पूरे किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू के तहत शुरुआत से कर्नाटक राज्य के लिए अब तक कुल 6,38,121 आवासों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5,73,160 आवास निर्माणाधीन है, जबकि 3,69,449 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

******